[Dr. Shrimati Rajinder Kaur] House that the New Delhi Municipal Commitiee Office employees are on strike for the last 15 days because of the anomaly in the emoluments of the employees of the same category, recruited on the same pattern with the same qualifications, doing the same type of work and being promoted in the same cadre but posted in differed departments. Those who went 1c Electricity and Water Departments get ex gratia payment and the others are being denied the same. This is a clear case of descrimination against the em ployees of the same institution. The office work of the NDMC stands <-+ill. The work of the International Vaccination Centre and the cash collection counters has also stopped, causing difficulties to the general public. The agitation has taken a serios turn. One employee, Shri Bindu Ram. who was on an indefinite hunger strike from the 24th April was rushed to the hospital on the 27th April. Another employee who had started a hunger strike was rushed to the hospital on the 8th May. Another employee, Shri Sunder Singh, has started a hunger strike from today. I will request the Home Minister to look into this matter and remove !.his anomally and discrimination to end the strike.

REFERENCE TO DISTRESS SALE OF COTTON IN THE COTTON GROWING STATES

श्री देवराज पाटील (महाराष्ट्र) : मान्यवर, सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से देश के एक महत्वपूर्ण वर्ग किसान की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । अनाज के बाद कपड़े का स्थान आता है और कपास से कपड़ा बनता है । इसलिए कपास के उत्पादक के हितों की रक्षा के बारे में अविलम्बनीय और सार्वजनिक महत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

सभापति जी, 22 दिसम्बर, 1977 को सदन में कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये मैंने तथा सभी दलों के सदस्यों ने उत्पादकों को कपास का लाभकारी मूल्य देने तथा कच्चे माल यानि कपास और तैयार उत्पादन यानि कपड़े की कीमतों में संतुलन कायम करने की मांग की थी । इस संदर्भ में सरकार को सलाह देने के लिये सरकार नियुक्त उच्चस्तरीय कमेटी हाई-पावर्ड कमेटी जिसका नाम है नक्सस कमेटी, उनके जो सुझाव थे कि कपड़े की कीमत से हम कपास की कीमत को लिंक कर सकते हैं । यह जो सुझाव दिया था कि रा-मटीरियल और एण्ड-प्राडक्ट में संतुलन किया जाए, जिससे हम कच्चे माल को रेम्युनरेटिव प्राइस दे सकते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया था । महत्व का दूसरा सुझाव सदन ने यह दिया था, मैंने नहीं, कि इस वर्ष के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये सरकार को क्या करना चाहिये, सदस्यों ने सुझाव यह दिया था कि भारतीय कपास निगम के काम को व्यापक बनाने और कपास के भावों को स्थिर करने में काटन कारपोरेशन की भूमिका को किसानों के हित में मजबूत करना चाहिए । इसके लिये कुछ सुझाव दिये थे और सरकार ने यह भी कहा था कि सरकार ने जो कपास की सपोर्ट-प्राइस फिक्स की है, वह रेम्युनरेटिव नहीं है । सभापति महोदय आप जानते हैं कि 19 अक्तूबर, 1977 में सरकार ने 1977–78 के लिए पंजाब एफ 420 वैरायटी की 255 रू० सपोर्ट-प्राइस तय की थी जो गत वर्ष से रू० 45 ज्यादा थी । लेकिन घोषित सपोर्ट-प्राइस के बारे में खुद कृषि मंत्री ने कहा था :

I quote from the news report: "He was, however, of the view !hat the support price of Rs. 255 a quintal was not realistic. He assured the House that efforts will be made to offer a realistic price."

दूसरा सुझाव जो उस वक्त हमने दिया था वह कपास के खरीदने के लिये था कि काटन कारपोरेशन हर मण्डी में जाकर

कपास की जो मार्केट प्राइस रहती है, उससे कुछ ज्यादा देकर कपास खरीद करे । सब कपास तो खरीद नहीं कर सकते, लेकिन 50 प्रतिशत खरीदें जिससे भाव स्टेडी रह सके ।

मैं आपकी घण्टी की आवाज़ सुन रहा हूं, दूसरे सवालों के लिए काफी समय दिया जाता है, तो किसानों के लिये जो महत्वपूर्ण विषय है, उसके लिये दो मिनट और दीजिये ।

MR. CHAIRMAN: All right, '.art please be brief.

श्री देवराव पाटील : दूसरा हमारा जो सवाल था कि काटन कार्पोरेशन को पैसे देकर मण्डी में भेज दें, उस पर उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नेन्डीज़ ने कहा था . . . मैं जो गवर्नमेंट ने प्रामिसिज़ दिये हैं, उसके बारे में कह रहा हूं । I quote from his speech: "The Industry Minister, Mr. George Fernandes, said that the Government would soon take a decision with regard to the operation of the Cotton Corporation of India which would make the Corporation a price stability force in the Cotton market."

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): It is not functioning like that.

श्री देवराव पाटील : सरकार ने दो आश्वासन दिये थे, नतीजा क्या है ? सभापति महोदय यह बात महत्व की है । किसान को तो यह बता दिया, देश को बता दिया कि हम किसान का हित करने वाले हैं, हम जनता सरकार हैं, इसलिये गत वर्ष जो कपास की सपोर्ट है उससे रू० 45 प्रति क्विंटल ज्यादा देंगे । यह तो बहुत अच्छी थी सरकार की घोषणा । लेकिन नतीजा क्या हुआ । सरकार को सपोर्ट प्राइस किसान को मिली क्या ? मैं इसलिये बता रहा हूं कि एक तरफ तो आश्वासन दिया गया, पर इसका नतीजा क्या हुआ ।

1 P.M.

rail in the prices of cotton for !he year 1977-78 in comparison to the pre-371 RS—7.

vious year. Sir, I quote:

"Wholesale prices of cotton for the year were lower in 1977-78 in comparison to 1976-77. The wholesale price Index of cotton for the financial year moved down by 2.4 per cent from 197.5 in 1976-77 to 192.7 in 1977-78."

और कपास निगम का रोल क्या रहा हैं वह मैं बताता हूं — The roll of Cotton Corporation of India has been procuring raw cotton at the existing market rates against indents placed on them by the National Textile Corporation. The Cotton Corporation of India participates in open auctions in the mandies—in some of the man-dis and not in all mandis.

Since September 1977 to April 15, 1978, the Corporation has purchased only 5.85 lakhs bales in all the ten cotton growing States, that is, the Corporation has purchased only 10 per cent in :;ome States and 5 per cent in Karanataka and 1 per cent in some of the States. What is the position today? There is no buyer in the market.

कपास की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कपास के भाव गत वर्ष से कम है । इसलिए इसमें काटन कारपोरेशन का रोल क्या रहा वह मैंने रिपोर्ट पढ़कर सुना दी ।

इस तरीके से नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन ने कपास खरीद लिया लेकिन अब उन्होंने काम बन्द कर दिया । काटन कारपोरेशन की खरीद न होने से आज कपास के भाव कम हो गये हैं । गुजरात का सवाल लीजिए, कर्नाटक का लीजिए, वहां पर भाव बहुत गिर गये हैं । कितने भाव गिर गये हैं वह मैं बताना चाहता हूं । लेकिन उससे गम्भीर समस्या उधार खरीदने की है । कभी नहीं हुआ वह इस बार हुआ । सब ने इस साल उधार कपास खरीदा, चाहे काटन कारपोरेशन आफ इंडिया हो चाहे फेडरेशन का सवाल हो,

[श्री देवराव पाटील]

चाहे मिल ओनर्स हों, चाहे ट्रेडर्स हों । सब ने कपास की खरीद किसान से उधार पर की है । किसान को पैसा एक दो महीने के बाद मिलता था । लेकिन अब रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि कुछ दलालों ने और ट्रेडर्स ने कपास की खरीद करके अपना दिवाला निकाल दिया है । दूसरी तरफ कपास निगम की खरीद न होने से भाव गिर गये हैं । न कारपोरेशन खरीदने के लिए तैयार है, न फेडरेशन खरीदने के लिए तयार है तो किसान क्या करे ? मिल ओनर्स ने दलालों की मार्फत किसानों से माल खरीदा किसानों ने उनको माल बेचा लेकिन उधार पर बेचा है और अब खबर आ रही है कि ट्रेडर्स ने अपना दिवाला निकाल दिया है । यह मैं साफ तौर से मंत्री महोदय के ध्यान में लाता हूं । हमारे जिस माल की खरीद की गई उसका पैसा पन्द्रह दिन के अन्दर उन सब लोगों को मिलना चाहिए और कपास की खरीदने में जो धांधली चल रही है, वह बन्द होनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है ।

REFERENCE TO THE MOVE TO CONVERT THE GANDHI HARI JIAN VIDYALAYA, DELHI INTO PUBLIC SCHOOL

SHRl L. R. NAIK (Karnataka): I had given a Calling Attention notice. I may be permitted to say briefly on it.

MR. CHAIRMAN: Mr. Khan. Will you be in a position to speak in three minutes?

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi); I will take only less than that.

SHRI L. R. NAIK: I will also finish in three minutes.

SHRl KHURSHED ALAM KHAN: I have to draw the attention of the hon. Home Minister to the unfortunate incident which has happened on the 5th of May, 1978, in the Gandhi Harijan Vidyalaya, which is a Government aided school in Delhi. This is a Government aided school where 3,600 students were studying with about 80 teachers. It appears that suddenly a decision was taken to convert this school into a public school. I do not know who took this decision and who approved of this decision. The result was that this resulted in the dislocation oi the work in the school and this incident has happened. I would like to know why this was allowed, particularly when 3,600 students were studying there. Now, after converting it info a public school, will it be possible for the poor parents of these students to Pay the high fees of the school and continue to keep their wards In the school? I suppose there is need for immediate action by the Delhi administration which has made a mess of the whole affair. They should immediately sort out this problem and the school should be reverted back as an ordinary aided school and *hese boy and 80 teachers should be given an opportunity to go back and Join their school.

MR. CHAIRMAN: The House will reassemble after lunch at 2.05 P.M.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at nine minutes past two of the clock, [The Vice-Chairman (Shri Arvind Ganesh Kulkarni in the Chair.]

THE FINANCE BILL, 1978—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I have to inform the Members that the Janata Party has got one hour and thirty-five minutes and there are three speakers. The same is the case with the Congress (I) Party—one hour and fourteen minutes and there are four speakers. So, I request that the time-allotment